शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में इसकी भूमिका

*डॉ. साधु राम गुर्जर

सारांश

ग्रामीण क्षेत्र हमारे देश की रीढ़ हैं, जहाँ अधिकांश जनसंख्या निवास करती है और यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालाँकि, औद्योगिकीकरण के कारण शहरीकरण में वृद्धि के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसर कम हो गए हैं। रोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या का पलायन इस विकासात्मक असंतुलन का प्रमुख कारण है। इस असंतुलन को कम करने और ग्रामीण आजीविका में सुधार करने के लिए रर्बनाइजेशन (Rurbanization) एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभरा है। यह शोध पत्र रर्बनाइजेशन की भूमिका का विश्लेषण करता है, जो ग्रामीण-शहरी पलायन को कम करने, ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण, शहरी, रर्बनाइजेशन, पलायन, जनसांख्यिकी लाभांश, विकास।

परिचय

शहरीकरण का अर्थ है जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण, जो आर्थिक अवसरों और रोजगार की वजह से होता है। शहरी क्षेत्रों को अवसंरचनात्मक विकास और आर्थिक उन्नति का लाभ मिलता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों की कमी, सुविधाओं का अभाव और रोजगार के अवसरों में कमी देखी जाती है। भारत, जहाँ अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, शहरी-ग्रामीण विभाजन को संतुलित करने में संघर्ष करता रहा है। इस अंतर को पाटने के लिए रर्बनाइजेशन की अवधारणा सामने आई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है।

रर्बनाइजेशन एक धीमी और अदृश्य प्रक्रिया है, जो कई बार भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक बाधाओं के कारण असमान होती है। शहरीकरण के साथ-साथ ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी और शहरी पलायन जैसी चुनौतियों को संबोधित करना आवश्यक है। इस शोध में रर्बनाइजेशन के माध्यम से ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को समझने और इसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

हस्तक्षेपों का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर बनाना है:

- स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- बच्चों, बुजुर्गों, विधवाओं और हाशिए पर स्थित समूहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना।
- ग्रामीण समुदायों के बीच जागरूकता फैलाना और उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में सशक्त करना।
- ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल, और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर ध्यान देना।

ये हस्तक्षेप ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को समृद्ध बनाने और उन्हें व्यापक आर्थिक ढांचे में शामिल करने का प्रयास करते हैं।

रर्बनाइजेशन में ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास रर्बनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का आधार बनता है। एक रर्बन क्षेत्र में शहरी आर्थिक विशेषताओं और जीवनशैली का समावेश होता है, जबकि यह अपनी ग्रामीण विशेषताओं को बनाए रखता है। रर्बनाइजेशन में ग्रामीण विकास के प्रमुख घटक हैं:

- स्वच्छ गाँव और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, जैसे सड़कें, पेयजल, और बिजली।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के तहत ग्रामीण सड़कों का विकास।
- ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) जैसी पहल के माध्यम से बाज़ार तक पहुँच।
- कृषि प्रसंस्करण उद्योगों और स्थानीय उद्यमों के माध्यम से रोजगार सृजन।

विभिन्न विकास योजनाओं के एकीकरण से ग्रामीण क्षेत्र पलायन को रोकते हुए फल-फूल सकते हैं। स्थानीय जनसंख्या की सक्रिय भागीदारी प्रभावी ग्रामीण परिवर्तन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

शहरीकरण और पलायन का प्रभाव

शहरीकरण के परिणामस्वरूप ग्रामीण श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शहरों की ओर पलायन हुआ है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी आयु वर्ग की कमी होती जा रही है, जबकि शहरी केंद्रों में जनसंख्या दबाव और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है।

पलायन के ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव निम्नलिखित हैं:

- श्रम की कमी: कृषि, जो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख आजीविका है, श्रमिकों की कमी से जूझ रही है।
- आर्थिक बोझ**: ग्रामीण परिवार शहरी क्षेत्रों से भेजी गई राशि (रेमिटेंस) पर निर्भर होते हैं, लेकिन इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वतंत्र रूप से नहीं बढ़ पाती।
- सामाजिक विस्थापन**: जैसे-जैसे लोग शहरों में जाते हैं, पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाएँ और सामुदायिक बंधन कमजोर होते जाते हैं।

रर्बनाइजेशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, संसाधनों तक पहुंच में सुधार करना, और स्थानीय प्रतिभाओं को बनाए रखना है।

प्रकरण अध्ययन: तेलंगाना

तेलंगाना, एक नवगठित राज्य, रर्बनाइजेशन की आवश्यकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के कई ग्रामीण गाँव विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जबकि शहरी केंद्रों, विशेषकर हैदराबाद, को अधिक प्राथमिकता दी गई है। इस असमान विकास के परिणामस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ।

तेलंगाना में रर्बनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण परिदृश्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। बुनियादी ढांचे के विकास, जैसे सड़क, बाज़ार और स्वास्थ्य केंद्र, पर ध्यान केंद्रित करके संतुलित विकास मॉडल अपनाया जा सकता है। इसके अलावा, कृषि प्रसंस्करण उद्योगों और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर तेलंगाना ग्रामीण जनसंख्या को आधुनिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर सकता है।

कार्यप्रणाली

यह अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करता है। सर्वेक्षणों के माध्यम से निम्नलिखित का मूल्यांकन किया गया:

- बुनियादी ढांचे, जैसे सड़कें, स्वच्छ पानी, स्कूल, और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता।
- ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता।
- ग्रामीण जनसंख्या की आर्थिक गतिविधियों, जैसे कृषि, लघु उद्योग, और सेवाओं में भागीदारी।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन का विश्लेषण इस बात के लिए किया गया कि यह कैसे समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी-स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना है, जबकि स्थानीय जनसंख्या को पारंपरिक ग्रामीण व्यवसायों में संलग्न करना है।

सरकारी हस्तक्षेप

रर्बनाइजेशन के लिए सरकारी नीतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख पहलकदमियों में शामिल हैं:

- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किफायती आवास।
- डिजिटल इंडिया: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और साक्षरता में सुधार।
- स्किल इंडिया: ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- MGNREGA: ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना, जिससे पलायन की आवश्यकता कम हो।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हो।

ये नीतियाँ, यदि प्रभावी ढंग से लागू की जाती हैं, तो ग्रामीण भारत में एक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन ला सकती हैं और ग्रामीण समुदायों को सतत विकास के लिए आवश्यक सुविधाएँ, कौशल और अवसर प्रदान कर सकती हैं।

निष्कर्ष

रर्बनाइजेशन ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार देने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, और रोजगार जैसी बुनियादी सेवाओं को ग्रामीण जनसंख्या तक पहुँचाकर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करता है और पलायन के दबाव को कम करता है। रर्बनाइजेशन महिलाओं और हाशिए पर स्थित समुदायों को सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, रोजगार और सामाजिक एकीकरण संभव हो पाता है।

रर्बनाइजेशन की सफलता के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, और ग्रामीण समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। यह बुनियादी ढांचे के विकास, पारदर्शी शासन, और ग्रामीण जनसंख्या की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। इस प्रकार, रर्बनाइजेशन भारत के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक हो सकता है।

***भूगोल विभाग**
राजस्थान विश्वविद्यालय

संदर्भ

1. बेंग्स, क्रिस्टर & श्मिट-थोमे, कैसा। (2006)। यूरोप में शहरी-ग्रामीण संबंध। हेलसिंकी विश्वविद्यालय।
2. चटर्जी, सुमना। (2014)। भारत में 'रर्बन' समाज: शहरीकरण के नए पहलू। IOSR जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 19(8), 14-18।
3. कुमार, रंजीत, उत्तम देब, आदि। (2014)। पूर्वी भारत में आर्थिक विकास और ग्रामीण परिवर्तन।
4. बर्डेग, जूलियो ए, टोमस रोसाडा, और एंथनी जे. बेबिंगटन। (2013)। ग्रामीण परिवर्तन।
5. कुंडू, अमिताभ, प्रधान, बसंता और सुब्रमणिया, ए। (2002)। द्वैतवाद या निरंतरता।
6. ग्रिफॉन, मिशेल। (2002)। ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में भविष्य के विकास की गतिशीलता।